कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ममता से और वार्ता की मांग

हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि पुलिस आयुक्त हटाने की मांग तो मान ली, स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों पर कार्यवाही बाकी है

कोलकाता, 18 सितंबर। पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों के आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत के लिए एक और दौर की मांग करते हुए बुधवार को भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी।

डॉ. अनिकेत महतो ने संवाददाताओं से कहा कि वे राज्य के मुख्य सचिव को ईमेल करेंगे और मुख्यमंत्री से एक और दौर की बातचीत की मांग करेंगे।

स्वास्थ्य सचिव को दंड देने की कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य स्वास्थ्य सचिवालय के बाहर नौवें दिन भी धरना दे रहे एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, हमने अपनी कुछ अधूरी मांगों और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री से और बातचीत का

- **उच्चतम न्यायालय के अनेक आग्रहों के बाद भी सरकारी अस्पतालों में 41 दिन से आउटडोर नहीं लग रहा है।**

अनुरोध किया है अस्पतालों में धमकी की संस्कृति ने माहौल को खराब कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय और बनर्जी ने बार-बार डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। डाक्टरों की हड़ताल से पिछले 41 दिनों से सरकारी अस्पतालों के रोगी विभागों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के तत्वावधान में मंगलवार रात डॉक्टरों ने एक आम सभा की और गत नौ अगस्त को आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने पर न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।

मंगलवार को मनोज कुमार वर्मा के कार्यभार संभालने के साथ ही कोलकाता पुलिस प्रमुख को बदलने की हडताली डॉक्टरों की मुख्य मांग को पूरा कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई।

गत 16 सितंबर को डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर बैठक की जो पांच घंटे से अधिक समय तक चली। इससे पहले ऐसी दो बैठकें बिना किसी नतीजे के विफल रही।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

एम.एन.आई.टी. के अठारहवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियाँ तथा स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में शिरकत की।

'यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, परन्तु नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहें'

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 में से 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलने पर प्रसन्नता जताई

- **एमएनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी शिरकत की और कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही ''युवा नीति-2024'' लाएगी।**
- **राष्ट्रपति मुर्मू ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर, 79 पी.एच.डी. विद्यार्थियों को डिग्री दी तथा नए बने छात्रावास का लोकार्पण भी किया।**
- **एम.एन.आई.टी. के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी ने संस्था का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि संस्था को शोध व अनुसंधान में 15 पेटेंट मिल चुके हैं।**

जयपुर, 18 सितम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को एम.एन.आई.टी. के 18 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्वभर में अग्रणी बने। इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शोध अनुसंधान में मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने, पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का आ ान किया। समारोह में 20 में से 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने संस्थान की फैकल्टी में एक तिहाई महिलाएं होने को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, ताकि इनके जरिए भारत तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़े।

राष्ट्रपति ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का लोकार्पण भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ''विकसित भारत 2047'' की जो संकल्पना संजोई है, उसका मूल आधार यही है कि देश सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बागडे ने एम.एन.आई.टी. में ''आर्टिफिशल इंटैलिजेंस'' विभाग की स्थापना की सराहना की तथा कहा कि युवा टेक्नोक्रेट्स के लिए आने वाले समय में इससे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे।

समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति-2024 तथा कौशल क्षमता विकास के लिए नई स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे युवाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने तथा उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को देश-विदेश के उत्कृष्ट सीईओ का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही, इसके तहत चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रूपए तक की फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर, भरतुपर, बीकानेर और उदयपुर में एक हजार करोड़ रूपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें।

एम.एन.आई.टी. के निदेशक प्रो. एन. पी. पाढी ने संस्था का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संस्थान को शोध और अनुसंधान में 15 पेटेंट मिले हैं।

1960-61 में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदर्शन को बल मिला। वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध, तेलंगाना और केरल का देश की जी.डी.पी. में योगदान 30 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट बताती है कि 1991 से पहले तक दक्षिणी राज्यों का खास योगदान नहीं था। उदारीकरण के बाद इन राज्यों ने तेजी से विकास किया इसके अलावा इन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय 1991 के बाद से राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल गई है। दक्षिणी राज्यों के अलावा रिपोर्ट में दिल्ली व हरियाणा का भी उल्लेख है, दिल्ली व हरियाणा ने भी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रदर्शित की है। पूरे अध्ययन काल में दिल्ली की प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक रही।

पेपर कहता है कि समुद्र किनारे वाले राज्यों ने सभी से बेहतर प्रदर्शन रहा जिसने अपवाद सिर्फ पश्चिम बंगाल है। वहीं बिहार की आर्थिक स्थिति गत दो दशकों में स्थिर रही है। हालांकि यह कई राज्यों से पीछे है। हमेशा कमी दर्शाने वाले ओडिशा की दशा में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। यह अध्ययन 1960-61 से 2023-24 के डेटा पर आधारित है। इससे पता लगता है कि समय-समय पर विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय व राज्यों की नीतियों पर कैसी प्रतिक्रिया दी।

''एक राष्ट्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर देश भर में चर्चा कराने का भी सुझाव दिया। एक कैबिनेट प्रैस रिलीज के अनुसार 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

देश की जी.डी.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1960-61 से 2023-24'' के अनुसार, प्रतिव्यक्ति आय को लेकर, कर्नाटक देश में तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि कर्नाटक में एक व्यक्ति की औसत आय, राष्ट्रीय औसत आय से 81 प्रतिशत अधिक है। एक तथ्य यह भी है कि राष्ट्रीय जी.डी.पी. में कर्नाटक का योगदान 8.2 प्रतिशत है।

आई.टी. के बाद, कर्नाटक स्पेस टेक्नोलोजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है तथा स्किल एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में भौतिक तथा मानवीय स्तर पर सामंजस्य बिठा रहा है। इस प्रकार, कर्नाटक स्पेस टेक्नॉलॉजी के प्रयासों में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है तथा इस तेजी से उभरते उद्योग पर फोकस कर रहा है।

कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस की सरकार होने के कारण, केन्द्र के कथित सौतेली माँ जैसे व्यवहार की अनदेखी करते हुए, कर्नाटक के पास स्पेस टेक्नॉलॉजी से अतिरिक्त आर्थिक लाभ सृजित करने के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। भारत का लक्ष्य है कि यह क्षेत्र स्पेस टेक्नॉलॉजी से आर्थिक कीमत के रूप में 17 अरब डॉलर से अधिक राशि अर्जित करे।

एक विशेषज्ञ का कहना है, ''हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय बाजार के अपने 40 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर आर्थिक मूल्य के रूप में 17 अरब डॉलर पैदा करें।''

इन प्रयासों को पूर्णता की ओर ले जाते हुए, कर्नाटक स्पेस टेक्नॉलॉजीज़ के लिए एक ''सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस'' स्थापित कर रहा है, जिससे नई तकनीकें विकसित हो सकें तथा स्टार्टअप्स एवं उद्यमों के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकें। यह पहल उस बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नई सुविधाओं और शैक्षिक सहयोगों के जरिए एयरोस्पेस तथा डिफेंस-मैन्यूफैक्चरिंग को बड़ा रूप देना है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सहयोग के फलस्वरूप इस बढ़ते हुए क्षेत्र के लिए कुशल कर्मचारी तैयार हो सकेंगे।

कर्नाटक के स्पेस टेक्नॉलॉजी सेक्टर की उत्तरोत्तर बढ़ रहीं क्षमताओं के प्रमाण के रूप में, बैंगलुरू स्थित स्टार्टअप ''पिक्सल'' को हाल ही में नासा के साथ एक अतिमहत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट सेटेलाइट डाटा एक्विजिशन प्रोग्राम का हिस्सा है।

जोधपुर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुलिस ने आरोपी नाबालिग को डिटेन कर बाल सुधारगृह भिजवा दिया है। शुरूआती जांच में सामने आया कि आरोपी को मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखने की आदत है। मासूम से रेप से पहले भी उसने ऐसे ही वीडियो देखे थे।

एम.डी.एम. हॉस्पिटल के डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कहा, मोबाइल पर वीडियो कंटेंट का कोई भी दायरा नहीं रहा है। दो साल की उम्र से बच्चे मोबाइल देखने के आदी हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों की मानसिकता को बदल रही है।

पुलिस निरीक्षक ने बताया कि गांव में 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का चोर सिपाही का गेम खेल रहे थे। लड़के ने मोबाइल पर एक गंदी साइट पर अश्लील हरकतें देखकर बच्ची से दुर्व्यवहार कर डाला।

जलेब चौक पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चौकीदार नियुक्त कर दिए, ताकि निगम मौके पर कब्जा न कर सके। दावे में गुहार की गई कि निगम को पाबंद किया जाए कि वह मौके पर कब्जा न करे और उन्हें बेदखल नहीं करे।

इसके विरोध में निगम की ओर से कहा गया कि राजघराने के लोगों ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ट्रस्ट का गठन किया है। जलेब चौक की खाली जमीन का उपयोग करने का अधिकार ट्रस्ट को नहीं है। जयपुर रियासत के राज्य सरकार में विलय के समय इसका सरकारी उपयोग करने के लिए कब्जा सरकार को दिया गया था।

वहीं कोवनांट के आधार पर सरकार ही इसकी सार-संभाल कर रही है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी।

अरावली के पहाड़ पर खनन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 18 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोबनेर के मेहस्वास गांव में अरावली पर्वतमाला में आने वाले गैर मुमकिन पहाड़ पर खनन को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव और खान निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश उम्मीद सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि जोबनेर के मेहस्वास गांव में अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत गैर मुमकिन पहाड़ आता है। राज्य सरकार ने यहां खनन की अनुमति दी है। जबकि अरावली के अन्तर्गत आने

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने जोबनेर के मेहस्वास गांव में अरावली पर्वतमाला में आने वाले गैर मुमकिन पहाड़ पर खनन के लिए मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव आदि को नोटिस भेजा है।**

के कारण यहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस गैर मुमकिन पहाड़ में गैर मुमकिन नदी का हिस्सा भी आता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन माफिया ने सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर पूरे 125 हेक्टेयर के पहाड़ का दोहन कर लिया है और अब यह समाप्त होने की कगार पर है। खनन माफिया तय क्षेत्र से अतिरिक्त स्थान पर भी खनन कार्य कर रहा है। खनन के दौरान विस्फोटकों का भी उपयोग किया जाता है। याचिका में गुहार की गई है कि यहां खनन कार्य रोका जाए और खननकर्ताओं से भारी पेनल्टी वसूली जाए।

मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

क्लेम अपील में पिता-पुत्र की उम्र में मात्र 6 साल का अंतर

जयपुर, 18 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना की क्लेम अपील में पिता-पुत्र की उम्र में सिर्फ छह साल का अंतर बताने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने प्रदेश के सभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वे क्लेम याचिका पेश होते समय ही दावेदारों और मृतक आदि के उम्र व जन्मतिथि से संबंधित आधार कार्ड के अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्व का कोई एक दस्तावेज पेश करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो दावेदारों से इस संबंध में शपथ पत्र लें। यदि वांछित दस्तावेज पेश नहीं किए जाएं तो क्लेम याचिका को खारिज किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि लंबित क्लेम याचिकाओं में भी अधिकरण जरूरी समझे तो इस संबंध में निर्देश दे सकता है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश डूंगाराम व अन्य की क्लेम याचिका को वापस लेने

- **हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानकर प्रदेश के सभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि क्लेम याचिका पेश होते ही दावेदारों और मृतक की उम्र सुनिश्चित करें।**

के आधार पर खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि अधिक क्लेम राशि लेने के लिए दुर्घटना के बाद मृतक या घायल के दस्तावेजों में जानबूझकर उम्र कम लिखाई जाती है। ऐसे में आश्रितों की उम्र को समायोजित कर वास्तविकता से कम लिखते हैं। जिससे भ्रष्ट आचरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस मामले में पिता-पुत्र में छह साल का अंतर बताया गया है। ऐसे में सिर्फ छह साल की उम्र में पिता बनना असंभव है।

मामले के अनुसार एम.ए.सी.टी. कोर्ट संख्या 2 जयपुर द्वितीय, ने 7 अगस्त, 2020 को अपीलार्थी डूंगाराम की पत्नी पार्वती देवी की दुर्घटना में मौत होने पर 7.71 लाख रुपए बीमा कंपनी को अदा करने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ डूंगाराम व उसके पुत्रों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि मृतका की उम्र 45 साल और उसके पति डूंगाराम की आयु चालीस साल बताई गई है। जबकि बेटे प्रदीप की उम्र 34 साल दर्शाई गई। अदालत की ओर से उम्र संबंधी अनियमिता पकड़ने पर अपीलार्थी ने इस अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए सभी दुर्घटना अधिकरणों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

नये कानूनों के तहत 5.5 लाख प्राथमिकी दर्ज हुई

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद साढ़े पांच लाख से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और आठ लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने के मौके पर बताया कि, एक जुलाई को भारतीय न्याय संहिता लागू किये जाने के बाद से तीन सितंबर तक कुल 5 लाख 56 हजार प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमित प्रशिक्षण और वेबिनार के माध्यम से 8 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत-म्यांमार सीमा पर 31 हजार करोड़ रूपये की बाड़ लगेगी

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए सरकार मैतेई तथा कुकी, दोनों समुदायों के साथ लगातार बात कर रही है और खुद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले सौ दिनों के दौरान मणिपुर में शांति बहाली एवं सुरक्षा के संबंध में अनेक विशेष कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से भारत-म्यामांर के बीच 1610 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और

- **सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी है।**
- **सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1610 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति दी है।**

सीमा सड़कों के निर्माण के काम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मोरेह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और मणिपुर में अन्यत्र 21 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।

मणिपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो बटालियनों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त वहां केन्द्रीय पुलिस बलों की लगभग 200 कंपनियां तैनात है।

मणिपुर सरकार ने आम लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 25 दुकानें तथा मोबाइल वैन चालू की हैं। ये दुकानें और मोबाइल वैन मणिपुर के सभी जिलों में कार्य कर रही हैं।

एक नई पहल के तहत, मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय पुलिस कल्याण केन्द्र आम लोगों के लिए खोले गए हैं। इस क्रम में 21 मौजूदा केन्द्रों के अलावा 16 नए केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। इन 16 नए केन्द्रों में से आठ घाटी में होंगे और शेष आठ पहाड़ी इलाकों में होंगे।

''वन नेशन, एक इलैक्शन'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रबल सम्भावना रहेगी। लेकिन, इस समय इस मुद्दे को सामने लाकर, भाजपा यह सपना सँजो रही है कि वह राजनैतिक माहौल को एक बार फिर से अपने पक्ष में कर लेगी।

भाजपा के थिंक टैंक के अनुसार, ओ.एन.ओ.ई. विपक्ष द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना की वकालत के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। मोदी के पहले दो कार्यकालों की स्थिति के विपरीत, इस समय राष्ट्रीय राजनैतिक एजेंडा तैयार करने का काम एक प्रकार से विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। ओ.एन.ओ.ई. के सहारे, भाजपा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले ट्रेंड की जगह पर पुनः प्रतिष्ठित होना चाह रही है। लेकिन मूल चुनौती यह है कि ओ.एन.ओ.ई. भाजपा की ''केन्द्रीयकृत एवं अधिनायकवादी राजनीति'' के खिलाफ विपक्ष के प्रचार-अभियान को और ज्यादा सशक्त बना देगा। विपक्षी नेताओं की ओर से कड़े विरोधी स्वरों की शुरुआत हो ही चुकी है। विपक्ष ओ.एन.ओ.ई. को भाजपा की एक ऐसी रणनीति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति पर एकल पार्टी प्रभुत्व स्थापित करना है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ओ.एन.ओ.ई. से संघवाद की भावना का अतिक्रमण होगा तथा यह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कमजोर कर देगा। अगर तथा जब कभी ओ.एन.ओ.ई. लागू होगा, कुछ राज्य सरकारों को, उन्हें संविधान-प्रदत्त पाँच साल के कार्यकाल का कुछ बाकी बचा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। यह सम्भव दिखाई नहीं देता कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री, खासतौर से वहाँ विपक्ष की सरकार होने की स्थिति में, अपने कार्यकाल के बकाया हिस्से की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जायेंगे।

राहुल पर भाजपा नेताओं की टिप्पणीः कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। कांग्रेस तथा उसके घटक संगठनों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस, भाजपा के नेताओं के बयान के खिलाफ सुबह से लामबद्ध है और पार्टी नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एनएसयूआई ने इसके विरुद्ध मार्च किया और चारों भाजपा नेताओं का पुतला फूंका। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले चार नेताओं के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

केजरीवाल सभी सरकारी सुविधायें छोड़ेंगे

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने का फैसला किया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों काम किए। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी?

सिंह ने कहा कि दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि पिछले दो साल से भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप खड़े किए, जबकि एक

- **आप पार्टी प्रवक्ता ने कहा, और नेता पद छोड़ने के बाद वर्षों सुविधायें भोगते हैं, पर केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे।**

रुपए का अभी तक सबूत नहीं मिला है। केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्लीवालों की सेवा की है।

आप नेता ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने तय किया कि, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं वे छोड़ देंगे। बाकी नेताओं को भी हमने देखा है कि अगर वे किसी पद पर पहुंच गए और सुविधा मिल गई तो पद छोड़ने के बाद भी उन सुविधाओं को पाने के लिए सालों तक लड़ाई लड़ते हैं।

सरकारी आवास से चिपके रहते हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपना सरकारी आवास खाली करने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल 15 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली कर देंगे।

सिंह ने कहा कि केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत से अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे।

अरविंद केजरीवाल हिन्दुस्तान के इतिहास में पहले नेता हैं, जो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर वोट मांग रहे हैं।

आतिशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब केजरीवाल ने, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही, एक रणनैतिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

केजरीवाल तथा मनीष सिसोदिया की निकटस्थ सहयोगी रहीं आतिशी ने मुख्यमन्त्री के रूप मे केजरीवाल को वापस लाने का संकल्प लिया है। उन्हें 26-27 सितम्बर को आहूत होने वाले दिल्ली विधानसभा के सत्र में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना होगा।

सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के बाद, आतिशी ने दिल्ली के नागरिकों के हितों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने केजरीवाल का बचाव करते हुए, उन पर लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताया तथा उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बचाने के लिए केन्द्र सरकार की एजेंसियों की आलोचना की।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908